उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–07(05/92)

मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की बैठक में 28.65 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी। इस धनराशि से हाथ और बिजली से चलने वाले चारा कटर दिया जाएगा। 5 सरकारी भेंड़ फार्म को मजबूत किया जाएगा। नए तरह के पॉल्ट्री और बायलर उत्पादन परियोजना से पशुधन का विकास किया जाएगा। बैठक में सचिव पशुपालन श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस

नोट–06(05/91)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में समाधान पोर्टल की समीक्षा की। बैठक में एनआईसी के अधिकारियों द्वारा समाधान पोर्टल का प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/वस्तुओं को प्रदान किये जाने में अड़चनरु/अनौचित्यपूर्ण विलम्ब, नियमविरूद्ध किसी भी अधिकारी के कार्य में अनियमतता, किसी योजना/कार्यक्रम में अनियमितता अथवा अक्रियान्वयन की शिकायत पर त्वरित एक्शन लेते हुए दो घण्टे के भीतर शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत का ऐक्नोलेजमेन्ट या पावती दिया जाय तथा देने के लिए समुचित तंत्र विकसित किया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सुझाव दिया कि समाधान पोर्टल के साथ ही जन शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु एक समेकित टोल फ्री नम्बर की शुरूआत के साथ राज्य एवं जिला स्तर पर कॉल सेन्टरस् स्थापित किये जाय। इसके साथ ही जन शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु सोशल मीडिया के अन्तर्गत वाट्सएप एवं इस प्रयोजन हेतु विकसित विशेष एपस् की भी सहायता ली जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा जन शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी तथा रिस्पॉन्सिव बनाने हेतु समाधान वेब पोर्टल, कॉल सेन्टर व्यवस्था तथा सोशल मीडिया का समेकन या इन्टिग्रेशन किया जायेगा। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यतः जन शिकायतों के निवारण हेतु त्वरित कार्यवाही व तीव्र एवं सकारात्मक रिस्पॉन्स पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जन शिकायतों के तीव्र निवारण हेतु समाधान वेब पोर्टल, कॉल सेन्टरस एवं सोशल मीडिया का अनुश्रवण शासन स्तर से एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनिशिचित किया जाय। मुख्यमंत्री जी के सुझावों के अनुसार प्राप्त जन शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु सम्बन्धित विभाग में भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पर्यटन राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में सशक्त एवं प्रभावी शिकायत तंत्र विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा सचिव मुख्यमंत्री ने समाधान पोर्टल में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा एवं एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(05/90)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकों आवंटित विभागों की समीक्षा करेंगे। इसका प्रारम्भ आज गुरूवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के विभागों की समीक्षा से हुआ।

सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुक्रवार 19 मई को कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक के शहरी विकास एवं आवास, मंगलवार 23 मई को कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य के परिवहन एवं समाज कल्याण, बुधवार 24 मई को कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रस्संकरण एंव उद्यान विभाग, शुक्रवार 26 मई राज्यमंत्री(स्वत्रंत प्रभार) श्रीमती रेखा आर्या के महिला कल्याण एवं बाल विकास, शनिवार 27 मई को राज्यमंत्री(स्वत्रंत प्रभार) डॉ.धनसिंह रावत के सहकारिता एवं उच्च शिक्षा विभाग, सोमवार 29 मई कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज के सिंचाई, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं पर्यटन, मंगलवार 30 मई को कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत के पेयजल एवं स्वच्छता तथा गन्ना विकास विभाग और बुधवार 31 मई को कैबिनेट मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय के विद्यालय शिक्षा, खेल, युवा कल्याण विभागों की समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि विभागों को निर्देश दिये गये कि प्राथमिकताओं और योजनाओं का पॉवर पांइट प्रेजेटेशन तैयार कर लें। माहवार लक्ष्यों को निर्धारित किया जाय। भारत सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर कार्यवाही और विवरण तैयार रखा जाय। विभागों का यदि कोई रिफार्म एजेंडा हो तो उसे भी प्रस्तुत किया जाय।

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(05/89)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर गहरा दुखः व्यक्त किया है। उन्होंने दिवगंत आत्मा की शांति एवं दुखः की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि श्री दवे जी एक समर्पित जन सेवक के रूप में याद किये जायेंगे। वह पर्यावरण सरंक्षण हेतु अत्यन्त उत्साही एवं समर्पित थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों ही रूपों में राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुयी है।

श्री माधव के निधन पर उनकों श्रद्धांजली देते हुए उनके सम्मान में गुरूवार को राज्य मुख्यालय पर, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां ध्वज को आधा झुका रखने का निर्णय लिया गया है।

नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक, सूचना : 7055007009

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(05/87)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास, कैन्ट रोड़ में उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ''मिल कर रहना'' शिविर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद् के कॉरपस फण्ड हेतु 25 लाख रूपयें की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राज्य के 12 जनपदों से शिविर में भाग लेने आये बच्चों का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, मिलजुल कर रहने आदतें एवं एक दुसरे के लिए त्याग की भावनाऐं विकसित करने में शिविर का अत्यन्त महत्व है। बच्चों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिविर का अर्थ है कि साथ–साथ रहना तथा शिविर में रहने के दौरान हम एक दूसरे की भावनाओं एवं इच्छाओं का सम्मान करना सीखते है। शिविर में बच्चें एक दूसरे से नई–नई बाते सीखते है तथा शिविर की समाप्ति पर एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ अनुभव करते है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में बच्चों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए स्वागत गान, देशभक्ति गान एवं गढ़वाली–कुमाऊॅनी लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने परिषद द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता के विजेता छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया।

कार्यक्रम को उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद के महासचिव श्री बालकृष्ण डोभाल ने भी सम्बोधित किया।

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(05/86)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर गहरा दुखः व्यक्त किया है। उन्होंने दिवगंत आत्मा की शांति एवं दुखः की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि श्री दवे जी एक समर्पित जन सेवक के रूप में याद किये जायेंगे। वह पर्यावरण सरंक्षण हेतु अत्यन्त उत्साही एवं समर्पित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 18 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(05/88)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में गुरूवार को कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत के साथ उनके विभागों, वन विभाग, श्रम एवं सेवायोजन, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा आयुष की समीक्षा की। बैठक से पहले मुख्यमंत्री और वन मन्त्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी।

वन विभागः–

वन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा चरागाह विकास, वृक्षारोपण की योजनाओं को मॉनिटर कैसे किया जा रहा है ? ''कागजों में हरियाली और मौके पर कोई काम नहीं'' ये स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। वन विभाग सभी वृक्षारोपण योजनाओं का आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए लगातार अनुश्रवण करें। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से पूछा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या कार्य योजना है ? उन्होंने कहा कि बंदरों और जंगली सुअरों से खेती को होने वाले नुकसान को रोकने के लिये ठोस प्रयास किये जाएं।

वन राजस्व की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने लीसा चोरी के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए पूछा कि यदि वन विभाग के डिपो से बिक्री नहीं हो रही तो लीसा की 100 से अधिक फैक्टरियां कैसे चल रही है। उनके द्वारा किये जाने वाला उत्पादन और वहां खपत हो रहे लीसे को को कौन क्रॉस चेक कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वन विभाग के सभी डिपों में एकत्र लीसे को पारदर्शी तरीके से नीलाम किया जाय। नीलामी प्रक्रिया को एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति द्वारा मॉनिटर किया जाय। बताया गया कि प्रदेश में वन विभाग कुल चार डिपों में 02.85 लाख कुन्तल लीसा नीलाम किया जाना है। इसी प्रकार वन विभाग द्वारा वर्तमान ट्रांजिट फीस 15 रुपए/टन को बेहद कम बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसको 50 रूपए/टन करने लिये कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिये सीमावर्ती प्रदेशों की शुल्क व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त टास्क फोर्स बना कर नियमित रूप में छोपमारी करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि जल्द ही वन, खनन, परिवहन और पुलिस की बैठक कर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिये और अधिक मजबूत पारदर्शी प्रवर्तन(इन्फोर्समेंट) व्यवस्था बनाई जाय। सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी करने के लिये यदि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीमें भी बनानी पड़े तो उसकी भी कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से निपटने के लिये फायर लाईन के रखरखाव के साथ ही स्थानीय समुदाय के साथ भी सहभागिता की जाय। प्री–फायर अलर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाय। उन्होंने कहा कि उरेडा द्वारा पिरूल से बिजली बनाने की, जो नीति बनाई गई है उसे प्रोत्साहित किया जाय। उन्होंने कहा कि पिरूल के अन्य उपयोगों के लिए भी नीति बनाई जाय और पिरूल का उठान प्रोत्साहित किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के लिये वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया तेज की जाय।

बैठक में कोटद्वार–रामनगर कंडी मार्ग पर भी विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मार्ग को प्रारम्भ करने के लिये प्रतिबद्ध है और इसके लिये सभी सम्भव विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यदि इसके लिये एलिवेटेड रोड बनानी हो अथवा ग्रीन रोड बनानी हो तो भी विचार किया जायेगा। यदि उत्तर प्रदेश कि सीमा में आने वाली भूमि के हस्तांतरण की जरूरत होगी तो उसका भी प्रयास किया जायेगा। उन्होंने वन मंत्री, मुख्य सचिव और वन विभाग के अधिकारियों को कंडी मार्ग हेतु सभी विकल्पों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई को जल संचय दिवस मनाया जायेगा और इसमें वन विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

श्रम एवं सेवायोजन विभागः–

श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नये कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये सेवायोजन विभाग के अधिकारियों को स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर(कौशल विकास अधिकारी) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग को सिर्फ कैरीयर काउन्सलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्लेसमेंट के कार्य के साथ–साथ युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरक ट्रेनिंग में भी आगे आना चाहिए। बैठक में बताया गया कि देहरादून में कूडा बीनने वाले 400 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनके पुनर्वास हेतु कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में श्रम निरीक्षकों के कार्य करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। श्रम विभाग के द्वारा पंजीकृत की जाने वाली दुकानों के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने हेतु शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रम रोकने के लिये कानून का सख्ती से पालन कराया जाय। व्यापारी संघों और होटल एसोसियेशनों को भी जागरूक किया जाय।

आयुष विभागः–

आयुष विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में वृहद कार्यक्रम आयोजित किये जाय। जनपदों में प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किये जाय। बैठक में आयुष विभाग से सम्बंधित कई मुद्दों, जैसे चिकित्सकों की उपलब्धता, फार्मेसियों का पुनरोद्धार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और शिक्षण स्टॉफ की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने की मांग पर भी विचार–विमर्श हुआ।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव मा.मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव आयुष श्री हरवंश चुघ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक, सूचना : 7055007009